तिब्बत देश

बीजिंग ओलंपिक के बाद चीन का एजेंडा ?

कई वर्षों से बीजिंग ओलंपिक को लेकर दुनिया भर में हलचल थी। एक ओर चीन सरकार इसके आयोजन को चीन के इतिहास का एक बड़ा मील का पत्थर मानते हुए इसे हर कीमत पर सफल बनाने के लिए उत्साहित थी। और दूसरी ओर मानवाधिकारों के पैरोकार इस बात से नाराज़ थे कि मानवाधिकारों को कुचलने वाली चीन सरकार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की पात्र नहीं है। ऐसे संगठनों ने अपनी इस नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए तिब्बत पर चीन के गैरकानूनी कब्जे, चीन में लोकतंत्रवादी आंदोलन के कुचले जाने, चीनी जनता की धार्मिक आजादी के हनन और आम चीनी नागरिकों के मूल अधिकारों के दमन जैसे कई मामलों की ओर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की। ऐसा करके वे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को यह समझाना चाहते थे कि चीन सरकार को बीजिंग में ओलंपिक खेलों के आयोजन का फैसला करके उसने ओलंपिक आंदोलन की भावनाओं के साथ इंसाफ नहीं किया। उनकी चिंता थी कि जिन मानवीय मूल्यों और मैत्री भावना को आगे बढ़ाने के लिए ओलंपिक खेलों की स्थापना की गई थी, आज की ओलंपिक समिति उन्हीं खेलों का आयोजन एक ऐसे देश को दे रही है जहां की सरकार इन मूल्यो को कुचलने के लिए दुनिया भर में कुख्यात है।

इस आंदोलन के जवाब में शुरू में तो ओलंपिक समिति और उसके अध्यक्ष जैक रॉग ने यही राग अपनाए रखा कि चीन के मानवाधिकारों के रिकार्ड को हम सब जानते हैं। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखकर हमने बीजिंग को 2008 के ओलंपिक के लिए इस आशा के साथ चुना है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की जिम्मेदारी मिलने से चीन सरकार को सभ्य दुनिया का सदस्य बनने और अपने मानवाधिकार रिकार्ड को सुधारने का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन चीन को ओलंपिक दिए जाने की घोषणा के बाद के छह साल में क्या हुआ इस सबको जैक रॉग ने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी।

कुछ उदाहरणों से पता चलेगा कि जिन उम्मीदों के साथ ओलंपिक समिति ने चीन को ओलंपिक के लिए चुना था उनकी चीन सरकार ने इस छह साल के दौरान क्या हालत बनायी है। सबसे खराब उदाहरण तिब्बत का है जिस पर चीन की सेना 1951 से जबरन कब्जा जमाए बैठी है। वहां की जनता की आजादी की आवाज़ को हमेशा के लिए कुचलने के लिए चीन सरकार कई साल से तिब्बत में हान चीनियों को बसाने का अभियान चला रही थी। इस अभियान को सबसे तेज़ गति इसी छह साल के दौरान दी गई। नतीजा यह है कि ल्हासा समेत सभी तिब्बती शहरों में लाखों की संख्या में हान चीनियों को बसाकर वहां तिब्बती जनता को अपने ही घर में अल्पसंख्यक बना दिया गया है। इस साल मार्च में जब तिब्बती जनता ने चीनी उपनिवेशवाद के खिलाफ आवाज़ उठायी तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए चीन सरकार ने अपनी सेना और पुलिस का जमकर इस्तेमाल किया। ओलंपिक के इतिहास में आजतक ऐसा नहीं हुआ कि अपने देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने से पहले वहां की सरकार 200 से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दे और उसके बाद भी ओलंपिक खेलों के आयोजन का सेहरा पहनकर इठलाती फिरे।

चीन सरकार ने ठीक ऐसी ही हरकत अपने उन नागरिकों के खिलाफ की जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और अपनी सरकार की मानवाधिकार विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते हैं। 1989 में तिएनअन मन चौक में चीन की कम्युरिस्ट सरकार ने किस तरह टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और मशीनगनों के बूते पर अपनी ही जवान बच्चों को कुचला था इसे आज पूरी दुनिया जानती है। चीन में लोकतंत्र लाने के इस अभियान को कुचलने के लिए आज दुनिया भर के विरोध के बावजूद मानवाधिकार और लोकतांत्रिक आंदोलन के नेता श्री हू जी जैसे हजारों लोग चीनी जेलों में सड़ रहे हैं। आज भी हर साल किसी न किसी बहाने गोली से मृत्युदंड पाने वाले चीनी नागरिकों की संख्या बाकी पूरी दुनिया में मृत्युदंड पाने वाले कुल लोगों के बराबर है।

इसे चीन सरकार की दादागीरी कहा जाए या ओलंपिक समिति और दुनिया भर की सरकारों का दब्बूपन कि ओलंपिक खेलों के दौरान अकेले बीजिंग शहर से ऐसे कई लाख चीनी नागरिकों को निकाल दिया गया जिनके घर की जमीन स्टेडियम आदि बनाने के लिए छीन ली गई थी। भला सभ्य दुनिया का इससे बड़ा मखौल क्या हो सकता है कि ओलंपिक के दौरान किसी चीनी या विदेशी नागरिक को किसी भी तरह का चीन सरकार विरोधी प्रदर्शन करने से रोकने के लिए पुलिस के सात लाख से ज्याद खुफिया एजेंट तैनात कर दिए जाए?

दुनिया भर की सरकारों और मानवाधिकार संगठनों के दबाव में चीन सरकार ने बीजिंग में तीन ऐसे स्थान निर्धारित करने की घोषणा की जहां पर ओलंपिक के दौरान प्रदर्शन किए जा सकेंगे। लेकिन इस अनुमति के साथ यह शर्त भी जोड़ दी कि प्रदर्शन करने वालों को पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी और हर प्रदर्शनकारी के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। हैरानी की बात है कि बाद में चीन सरकार की ओर किए जाने वाले जुल्मों के खतरे से वाकिफ होने के बावजूद तीन विदेशियों समेत 149 लोगों ने 77 आवेदन देने का साहस दिखाया। लेकिन मजेदार बात यह रही कि ओलंपिक के आखिरी दिन तक इनमें से एक को भी अनुमति नहीं दी गई। उलटे हुआ यह कि आवेदन देने वालों को पुलिस जांच के नाम पर जमकर धमकाया गया और प्रताड़ित किया गया। आखिरकार 74 प्रदर्शनों के आवेदन वापस ले लिए गए। लेकिन इस सबके बावजूद ओलंपिक के दौरान बीजिंग में कई दर्जन प्रदर्शन हुए। यह बात अलग है कि ऐसा कोई प्रदर्शन होते ही वहां चप्पे–चप्पे पर तैनात चीनी एजेंटों ने प्रदर्शनकारियों को दबोच लिया और फोटो लेने वाले विदेशी पत्रकारों की भी जमकर धुनाई की।

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनियों और 'रिपोटर्स विदाउट बॉडर्स' जैसे संगठनों ने जब ओलंपिक समिति के सामने इन शिकायतों को रखा तो समिति के अधिकारी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाए कि वे इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में जानते हैं और इस बात से आहत हैं कि चीन सरकार ने मानवाधिकारों और मानवीय स्वतंत्रता के जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाना बाकी हैं

और अब ओलंपिक खत्म होने के बाद हालत यह है कि चीन सरकार का ओलंपिक कराने का सपना न केवल पूरा हो चुका है बल्कि उसके सफलता पूर्वक पूरा होने से उसे वे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक फल भी हासिल हो गए हैं जिसकी वह असल में हकदार नहीं थी। इस आयोजन के माध्यम से चीन सरकार ने पूरी दुनिया को, खासतौर से मानवाधिकार संगठनों को यह संदेश दे दिया है कि अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत के बूते पर वह कुछ भी हासिल कर सकती है।

अब ओलंपिक पूरा होने के बाद चीन सरकार के सामने अगला लक्ष्य तिब्बत, सिंकियांग (पूर्वी तुर्किस्तान) और भीतरी मंगोलिया जैसे उपनिवेशों की मूल पहचान को खत्म करके उनका पूरी तरह चीनीकरण करना है। इस मामले में अब उसके सामने दुनियादारी और दिखावे की वह मजबूरी भी नहीं है जो ओलंपिक के कारण उसकी राह का रोड़ा बनी हुई थी। ताइवान के मामले में भी अब चीन सरकार की हालत ओलंपिक से पहले वाले के दौर के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। नए आत्मविश्वास वाले इस वातावरण में वह ताइवान के खिलाफ कड़ा सैनिक दुस्साहस भी दिखाने का फैसला कर सकती है जिसकी अब तक वह केवल धमकियां देती रही है। ऐसे हालात में दुनिया भर की सरकारों और लोकतंत्र तथा मानवाधिकार संगठनों की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई है। अब विश्व की सभ्य बिरादरी के सामने एक ऐसी चुनौती है जिससे मुंह मोड़ना बहुत महंगा पड़ सकता है।

– विजय क्रान्ति

बीजिंग में एपी के फोटोग्राफर को घसीटते चीनी एजेंट : चीनी दादागीरी

बीजिंग ओलंपिक में मानवाधिकार और प्रायोजक कंपनियों की शर्मनाक भूमिका

ह्यूमन राइट्स वॉच ने कारपोरेट प्रायोजकों की नैतिकता पर गंभीर सवाल उठाए

पिछले 12 महीनों में ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य समूहों ने बार–बार प्रमाणित किया कि बीजिंग ओलंपिक अभी तक 'अच्छाई की ताकत' के पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। बीजिंग तक की दौड़, चीन में मानवाधिकार उल्लंघन के बढ़ रहे मामलों से कलंकित हुई है।

न्यूयार्क मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि बीजिंग ओलंपिक के प्रमुख कार्पोरेट प्रायोजक अपने ही बनाए हुए कापोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर कायम नहीं रह पाए। ये प्रायोजक बीजिंग ओलंपिक खेलों से संबंधित मानवाधिकारों के अपमान पर स्वयं या सामूहिक रूप से आवाज उठा पाने में असफल रहे। अब उन्हें ओलंपिक में मानवाधिकारों के अपमान पर नजर रखने के लिए ओलंपिक समिति में एक स्थाई निकाय के गठन का समर्थन करना होगा।

बीजिंग ओलंपिक के शीर्ष 12 प्रायोजक (द ओलंपिक पार्टनर) थे – एटॉस ओरिजिन, कोका–कोला, जनरल इलेक्ट्रिक, मैन्यूलाइफ, जॉनसन एंड जॉनसन, कोडक, लेनोवो, मैकडोनल्ड्स, ओमेगा (स्वाच ग्रुप), पैनासोनिक, सैमसुंग और वीज़ा। पिछले 12 महीनों से ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन सभी शीर्ष प्रायोजकों से बीजिंग ओलंपिक से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई मामले में बार–बार संपर्क किया और इनमें से पांच कंपनियों से ऑफ द रिकार्ड मिली भी। शेष सातों ने तो बार बार के अनुरोध के बावजूद जवाब तक नहीं दिया। इसमें मीडिया पर सेंसरशिप, ओलंपिक स्थलों को निर्माण करने वाले प्रवासी मजदूरों के शोषण और इन स्थलों के निर्माण के लिए सैकड़ों चीनी नागरिकों को उनके घरों से उजाड़ने के मामले शामिल हैं। लेकिन प्रायोजक इन मामलों को उठाने के प्रति अनिच्छुक दिखे।

ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया एडवोकेसी डायरेक्टर सोफी रिचर्ड्सन ने कहा, ''ओलंपिक प्रायोजक अच्छे कार्पोरेट नागरिक होने का दावा करते हैं। किंतु जिस तरह ओलंपिक स्टेडियम की अपनी आरामदेह सीटों से वे खेलों का मजा लेते हैं, उन्हें दर्शाना चाहिए कि वे स्टेडियम और होटल बनाने वालों, उनके होटलों के कमरों को साफ करने वालों, खाना परोसने वाले चीनी नागरिकों, या उनके समाचार छापने का प्रयास करने वाले चीनी पत्रकारों के बारे में बोल पाने में नाकाम रहे।''

एक कार्पोरेट एक्जीक्यूटिव ने ह्यूमन राइट्स वॉच से कहा, ''देशों की आलोचना करने के लिए हमारे लिए यह उपयुक्त स्थल नहीं है।'' दूसरे ने कहा, ''यह तो मानवाधिकार से जुड़ी संस्थाओं का काम है।'' इस तरह के बयान अनेक शीर्ष प्रायोजकों की वेबसाइट पर दर्शाई गई कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की नीतियों का खंडन करते हैं। उदाहरण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक्स की वेबसाइट का जीई सिटीजनशिप खंड घोषित करता है कि जीई मानवाधिकारों के मामले में अपने ग्राहकों व आपूर्तिकर्ताओं के साथ रिश्तों और समुदायों व सरकारों के साथ हमारे रिश्तों के माध्यम से एक उदाहरण बनना चाहता है।'' लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक्स के अधिकतर ग्राहक चीनी नागरिक ही हैं जो सुनियोजित प्रताड़ना के शिकार हैं।

मानवाधिकारों के अपमान पर ओलंपिक प्रायोजकों की चुप्पी बड़ी स्पष्ट है क्योंकि इन सभी ने शीर्ष स्पांसर्स का दर्जा हासिल करने के लिए कुल 86 करोड़ 60 लाख अमरीकी डॉलर खर्च किए हैं। ह्यूमन राइट्स वाच ने शीर्ष ओलंपिक प्रायोजकों से उनके कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों के प्रति किए गए वादों के अनुरूप छह विशेष कदम उठाने का आग्रह किया है।

1. ओलंपिक चार्टर के मानवाधिकार संबंधी आयामों के प्रति खुल कर बोलेंगे जो सार्वभौम मौलिक जातीय सिद्धांतों के सम्मान और मानवीय अस्मिता की संरक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं।
2. सार्वजनिक तौर पर प्रमाणित करें कि चीन में चल रहे उनके काम से श्रमिकों के शोषण या अन्य अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।।
3. ओलंपिक आयोजन की अनुमति मिलने के समय मानवाधिकारों के प्रति किए गए वादों, विशेषकर मीडिया की स्वतंत्रता को निभाने का चीनी अधिकारियों से आग्रह करेंगे।

4. 'द रियल चाइना एंड द ओलंपिक्स' शीर्षक वाले खुले पत्र के सह लेखक हू जियांग की तरह मानवाधिकारों से जुड़े गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई की अपील करेंगे।

5. मार्च 2008 में तिब्बत में हुए बर्बर दमन की स्वतंत्र जांच का समर्थन करें (विशेषकर मशाल दौड़ के तिब्बत से होकर गुजरने के प्रायोजक कोका कोला, लेनोवो और सैमसंग पर केंद्रित)।

6. भावी आयोजक देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन से निपटने के लिए आईओसी पर एक स्थाई समिति स्थापित करने या कोई तरीका विकसित करने का दबाव डालें।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि उपरोक्त सुझावों पर किसी भी ओलंपिक प्रायोजक ने सार्थक ढंग से कोई पहल की है। इस निष्क्रियता से इन कंपनियों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत खंडित हो जाते हैं जिनका वर्णन उनकी वार्षिक रिपोर्टों व वेबसाइट्स पर किया गया है। इनमें बिजनेस लीडर्स इनिशिएटिव ऑन ह्यूमन राइट्स (बीएलआइएचआर)) द्वारा तय मानक शामिल हैं जिसके सदस्य जनरल इलेक्ट्रिक व कोकाकोला भी हैं। मशाल दौड़ की एक प्रायोजक कोकाकोला ने मशाल के तिब्बत प्रवेश की वकालत की थी, यह जानते हुए भी कि वहां चीन सरकार ने मार्च 2008 में प्रदर्शनों का किस तरह हिंसक दमन किया था और मीडिया का गला घोंट दिया था।

कोकाकोला के चेयरमैन ने विल्ले इसडेल ने 7 जुलाई को बीबीसी से कहा था, ''मुझे विश्वास है कि ओलंपिक खेल अच्छाई की एक ताकत हैं और यदि वे अच्छाई की ताकत नहीं हैं, तो हमें इन्हें नहीं प्रायोजित करना चाहिए।

पिछले 12 महीनों में ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य समूहों ने बार–बार प्रमाणित किया कि बीजिंग ओलंपिक अभी तक 'अच्छाई की ताकत' के पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। बीजिंग तक की दौड़, चीन में मानवाधिकार उल्लंघन के बढ़ रहे मामलों से कलंकित हुई है। यही नहीं, 8 अगस्त को खेलों के उद्घाटन के बाद चीन सरकार ने मानवाधिकार समर्थकों के दमन का अभियान तेज कर दिया है, उन्हें धरना स्थलों पर जाने से रोक दिया है, और मीडिया व इंटरनेट को स्वतंत्रता के वादे से मुकर गई है। ओलंपिक दौड़ के समय विदेशी पत्रकार पीटे गए, हिरासत में लिए गए तथा उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई। बीजिंग की सड़कों से हजारों अवांछित लोगों को बलपूर्वक खदेड़ा गया, जिनमें भिखारी, याचिकाकर्ता और प्रवासी मजदूर शामिल थे।

ल्हासा के मुख्य मंदिर जोखांग के बाहर चीनी सैनिक : दमन के औजार

ओलंपिक से उत्साहित चीन ने तिब्बत में दमन का सिलसिला तेज किया

इंटरनेशनल कैंपेन फार टिबेट की नई रिपोर्ट

शांतिपूर्ण ओलंपिक का ढिंढोरा पीटने के बाद चीन ने तिब्बत में दमन का सिलसिला तेज कर दिया है। लेकिन दुनिया से अपनी इन हरकतों से छिपाए रखने और तिब्बत में दमन पर पर्दा डालने के लिए चीन ने पूरे तिब्बत को सील कर रखा है। और यह सब इस सबके बावजूद हो रहा है कि ओलंपिक के नियमों के मुताबिक चीन सरकार ने मानवाधिकारों की बेहतरी और खुलेपन का वादा कर रखा है। चीन सरकार ने तिब्बत के समाचारों पर भी प्रतिबंध लगा रखा है।

तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान 'इंटरनेशनल कैंपेन फार टिबेट' ने एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें इस साल मार्च में शुरू हुई तिब्बती जनक्रान्ति से पैदा हुई स्थिति की विस्तृत जानकारी पेश की गई है। ''तिब्बत एट ए टर्निंग प्वाइंट – द स्प्रिंग अपराइज़िंग एंड चायनाज़ यू क्रैकडाउन'' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में चीन के ताजा दमन के कई सबूत दिए गए हैं। इनसे जो विवरण सामने आता है वह कुछ इस प्रकार है:

– हिरासत में लिए गए सैकड़ों तिब्बती चरम बर्बरता के शिकार। इनमें भिक्षु, भिक्षुणियां और स्कूली बच्चे भी शामिल हैं।

– अनाम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी जिन्हें गोली मार दी गई, और ऐसे लोगों के नाम जो उत्पीड़न के चलते जेलों में मर गए या अत्याधिक बर्बरता या फिर दलाई लामा का अपमान करने को मजबूर होने के बाद की

चीन ने तिब्बत में दमन का सिलसिला तेज कर दिया है। लेकिन दुनिया से अपनी इन हरकतों से छिपाए रखने और तिब्बत में दमन पर पर्दा डालने के लिए चीन ने पूरे तिब्बत को सील कर रखा है। ओलंपिक नियमों के मुताबिक चीन सरकार ने मानवाधिकारों की बेहतरी और खुलेपन का वादा कर रखा है।

ग्लानि के कारण आत्महत्या कर बैठे।

– समूचे तिब्बती पठार पर 125 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन हुए जिनमें से ज्यादातर अहिंसक थे। तिब्बतियों ने अपने जान की बाजी लगाकर दिखाया कि निर्वासित तिब्बती नायक दलाई लामा ही तिब्बती हितों के असली प्रतिनिधि हैं न कि चीनी साम्राज्य।

– असंतुष्ट भिक्षुओं के प्रदर्शनों को देखते हुए मठों से उनका सफाया करने के लिए नए कठोर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिनमें उपासना पर रोक लगाना और ऐसे कदम शामिल हैं जो तिब्बती बौद्धमत पर सुनियोजित ताजा प्रहार का संकेत है। यह अभियान चीनी नेता हू जिंताओ के व्यक्तिगत नेतृत्व में चलाया जा रहा है और सांस्कृतिक क्रांति की याद दिलाता है।

निर्वासित तिब्बती सरकार के अनुसार ड्रेपुंग मठ से जुड़े एक मंदिर में आजकल चीनी सशस्त्र बलों का कड़ा पहरा है। वहां के भिक्षुओं को अंदर बंद रखा जा रहा है और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है।

एक स्थानीय तिब्बती ने अपनी पहचान बताने से मना करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि सेरा मठ जिसे पहले खोल दिया गया था, उसे भी बिना कारण बताए दोबारा बंद कर दिया गया है। उसने बताया कि ल्हासा के सभी प्रमुख स्थानों पर सेना का पहरा है। ड्रेंपुंग मठ को फोन लगाने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता।

तिब्बत में 14 मार्च से शुरू हुई जनक्रान्ति के बाद चीनी अधिकारियों ने तिब्बती बौद्ध मठों में भिक्षुओं के लिए कथित 'देशभक्ति परक शैक्षिक कार्यक्रम' में भाग लेना जरूरी कर दिया। इसके बाद बहुतेरे भिक्षुओं ने तो मठ छोड़ने का ही फैसला कर लिया। एक भिक्षु केलसांग के अनुसार, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने हाल ही में पर्यटकों की सुविधा के लिए और तिब्बत में साहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के नाम पर सभी बौद्ध भिक्षुओं से मठों में लौटने का फरमान जारी किया है।

तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान आईसीटी विश्व के नेताओं पर दबाव डाल रहा है कि वे तिब्बत में हुए प्रदर्शनों में शामिल उन एक हजार से अधिक लोगों के बारे में चीन से जवाब तलब करें जो लापता हैं। राष्ट्रपति हू जिंताओ तिब्बत में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुआई में लागू की जाने वाली उन कड़ी नीतियों को बनाने वालों में शामिल थे, जिनके कारण तिब्बत में जनक्रान्ति का जन्म हुआ। आईसीटी ने कहा है कि इस संकट को हल करने के लिए राष्ट्रपति हू तिब्बत के भविष्य पर सीधे दलाई लामा से बात करें, जिन्हें विश्वभर ने तिब्बतियों का मुख्य प्रतिनिधि माना है।

तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान ने विश्व के नेताओं पर दबाव डाला है कि वे तिब्बत में हुए प्रदर्शनों में शामिल उन एक हजार से अधिक लोगों के बारे में चीन से जवाब तलब करें जो लापता हैं। इस गहराते संकट को हल करने के लिए राष्ट्रपति हू से विनती करनी चाहिए कि वह तिब्बत के भविष्य पर सीधे दलाई लामा से बात करें, जिन्हें विश्वभर ने तिब्बतियों का मुख्य प्रतिनिधि माना जाता है।

ओलंपिक के दौरान विरोध जताने की अनुमति नहीं

खुलेपन के चीनी वादे धरे रहे

बीजिंग, 18 अगस्त ओलंपिक खेलों के दौरान विरोध जताने के लिए चीन सरकार को 77 अनुरोध आए, पर दो को छोड़कर अब तक शेष सभी खारिज कर दिए गए हैं। रोचक बात यह है कि ओलंपिक शुरू हुए दस दिन हो चुके हैं और केवल छह दिन बचे हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के अनुसार जिन दो आवेदनों पर अभी विचार होना है वे भाग लेने वालों की पात्रता के बारे में अधिक जानकारी और अपेक्षा के अनुरूप समुचित कागजात के लिए रोके गए हैं।

चीन को ओलंपिक खेल आयोजित करने का सम्मान दिए जाने पर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने यह कहकर विरोध किया था कि वहां लोगों को मूलभूत मानवाधिकार नहीं दिए गए हैं। इस पर ओलंपिक समिति ने कहा था कि चीन को यह सम्मान इस उम्मीद से दिया गया है कि इससे चीनी शासकों को अपने यहां मानवाधिकारों की हालत सुधारने की प्रेरणा मिलेगी।

शिनहुआ एजेंसी ने एक अनाम प्रवक्ता का हवाला देते हुए बीजिंग पब्लिक सेक्यूरिटी आफिस में बताया कि आधिकारिक तौर पर घोषित तीन धरना स्थलों पर प्रदर्शन के लिए आए बाकी 74 आवेदन वापस ले लिए गए ''क्योंकि आवेदकों की शिकायतों को संबंधित अधिकारियों या विभागों ने मिल बैठकर सुलझा लिया था। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि तीन विदेशियों सहित कुल 149 लोगों ने विरोध जताने के लिए आवेदन दिए थे।

धरना स्थलों के बारे में लगातार पूछताछ के बावजूद ओलंपिक खेल शुरू होने के 11वें दिन चीनी अधिकारियों ने ये तथ्य उजागर किए। कुछ बातें तो हवा में तैर भी रहीं थी, जिन्हें पत्रकारों और मानवाधिकार समूहों ने स्वतंत्र रूप से उजागर कर दिया था। उदाहरण के लिए, चीनी नागरिकों को विरोध जताने संबंधी आवेदन जमा करने से जबरन रोकने के कई मामलों की व्यापक गूंज हुई। यही नहीं, ऐसे आवेदकों को पुलिस द्वारा उठा लिए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। उन्हें संभवतः जेल भेज दिया गया है। खबरें हैं कि प्ले कार्ड लिए हुए कुछ चीनियों ने बिना अनुमति लिए एक कोशिश की जिसे पुलिस ने विफल कर दिया।

ओलंपिक खेल शुरू होने के बाद अब तक मुक्त तिब्बत की मांग को लेकर कई स्थानों पर विदेश से

आए तिब्बत समर्थकों ने नाटकीय ढंग से विरोध जताया। लेकिन इन लोगों को पकड़ कर चीन से बाहर निकाल दिया गया। प्रदर्शन करने वालों में कनाडा, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन समेत कई देशों में काम करने वाले तिब्बत समर्थक संगठन थे। इनमें सबसे जोरदार भूमिका 'स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री टिबेट' की थी जो दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों में सक्रिय है।

हालांकि ओलंपिक के नियमित प्रेस सम्मेलनों में खाली धरना स्थलों के बारे में लगातार सवाल उठाए गए, लेकिन न तो बीजिंग आयोजन समिति, न ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इस बारे में कुछ बताने को इच्छुक दिखी। आईओसी की प्रवक्ता गिसेल डेविस ने बार–बार धरना स्थलों की जिम्मेदारी बीजिंग सिटी गवर्नमेंट पर थोपी। लेकिन एक बात उन्हें माननी पड़ी, ''अब तक सार्वजनिक तौर पर जो घोषित किया गया है, वास्तव में वैसा होता हुआ दिखता नहीं है और ढेरों सवाल पूछे जाने हैं। आईओसी चीनी अधिकारियों से इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है।''

खेलों की शुरूआत से पहले चीनी प्रचार मंत्रालय द्वारा चीनी मीडिया को जारी किए गए 21 शासनादेशों में धरना स्थलों को विशेष रूप से शामिल किया गया था। घोषित किया गया था, ''तीनों धरना स्थलों पर किसी साक्षात्कार और कवरेज की अनुमति नहीं होगी।'' लेकिन न्यूयार्क स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच तथा अन्य द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है कि ये धरना स्थल महज ढोंग हैं।

एचआरडब्लू के हांगकांग स्थित एक कनाडियन शोधकर्ता फेलिम किने ने आरोप लगाया कि ''बीजिंग ओलंपिक के तथाकथित धरना स्थल वास्तव में पूर्व के ओलंपिक शहरों में सार्वजनिक विरोध और मीडिया व इंटरनेट की स्वतंत्रता के लिए की गई व्यवस्था की फूहड़ अनुकृति भर है। वास्तविकता यह है कि अधिकारी खेलों के दौरान स्थिरता और सुव्यवस्था का मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश में उन अधिकारों की जमकर खिल्ली उड़ाते रहे।''

शिनहुआ की रिपोर्ट के अनुसार जिन चीनी नागरिकों ने विरोध जताने के लिए आवेदन दिए थे, उनके मुद्दे श्रमिक विवाद, चिकित्सा विवाद, या अपर्याप्त कल्याण जैसे थे। तो भी इस रिपोर्ट में विदेशी पत्रकारों द्वारा उठाए गए मामलों मसलन घर उजाड़ने या अफसरों के दोषपूर्ण व्यवहार या फिर सिचुआन भूकंप में अपने बच्चे खो देने के बाद भी घटिया स्कूल निर्माण जिसके चलते हादसा हुआ, के खिलाफ चीनियों की विरोध जताने की इच्छा कुचल देने का जिक्र नहीं था।''

इंटरनेट का कमाल –– बीजिंग में 18000 'वर्चुअल' प्रदर्शनकारी

दुनिया भर से प्रदर्शनकारी इंटरनेट पर

17 अगस्त, बीजिंग में सरकार द्वारा तय किए गए तीनों सरकारी प्रदर्शन स्थल भले ही खाली रहे हों, लेकिन मानवाधिकारों और इंटरनेट प्रेमी कार्यकर्ताओं ने चीन सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने का रास्ता ढूंढ़ ही निकाला। 17 अगस्त तक 18,100 से अधिक लोग चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव के विरूद्ध आनलाइन विरोध जता चुके थे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दबाने पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ और राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए फ्री प्रेस के समर्थकों ने खेलों के उद्घाटन समारोह से पहले आनलाइन प्रतीकात्मक विरोध को भी हवा दी। कोई भी प्रतीक प्रदर्शनकारी पांच प्ले कार्ड्स में से एक चुन सकता था। इन पर नारे लिखे थे, ''मैं ओलंपिक समारोह का बहिष्कार करता हूं।'' ''खेल के लिए हां, दमन के लिए ना, '' ''स्वतंत्रता नहीं तो ओलंपिक खेल भी नहीं'', ''ओलंपिक के आदर्शों से विश्वासघात में आईओसी सहभागी,'' और ''ओलंपिक कैदियों को रिहा करो।'' बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम के सामने इस असाधारण धरने में शामिल होने के बाद नारा लिखा हुआ एक प्ले कार्ड मिलने के बाद आप नेट पर यह भी देख सकते हैं कि दूसरे कौन लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

ये प्रतीक प्रदर्शनकारी सभी ओलंपिक बंदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं ह्यूमन राइट्स अटार्नी गाओ जिसेंग। वे गरीबों, एड्स पीड़ितों, याचिकाकर्ताओं और फालुन गोंग के समर्थन में खड़ा होने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें पिछले साल नवंबर में पब्लिक सेक्यूरिटी ब्यूरो पुलिस पकड़ ले गई थी। गाओ के परिवार के एक नजदीकी सूत्र ने बताया कि उन्होंने दो महीने जबर्दस्त उत्पीड़न की त्रासदी झेली। उनकी केवल पिटाई ही नहीं हुई, बल्कि चीनी गार्ड्स ने उन पर पेशाब भी किया। श्री गाओ को ओलंपिक तक बीजिंग से बाहर निकाल दिया गया है।

दूसरे विरोधी हैं हू जिया। वह भी चीनी ह्यूमन राइट्स अटार्नी हैं। उन्हें पिछले साल विद्रोह के आरोप में साढ़े तीन साल की जेल हुई थी। ओलंपिक उद्घाटन समारोह के अगले दिन उनकी पत्नी लापता हो गईं। आशंका है कि पुलिस ने उन्हें पकड़ रखा है।

कोई भी प्रदर्शनकारी पांच प्ले कार्ड्स में से एक चुन सकता था। इन पर नारे लिखे थे, ''मैं ओलंपिक समारोह का बहिष्कार करता हूं।'' ''खेल के लिए हां, दमन के लिए ना, '' ''स्वतंत्रता नहीं तो ओलंपिक खेल भी नहीं'', ''ओलंपिक के आदर्शों से विश्वासघात में आईओसी सहभागी,'' और ''ओलंपिक कैदियों को रिहा करो।''

फोटो : विजय क्रान्ति

हिमकैट की प्रार्थना सभा में लामा ज़ोत्पा और भिक्षु :अहिंसा में आस्था

तिब्बत के समर्थन में हिमकैट का शांतिमार्च

एक सप्ताह के अनशन में भी शामिल

इस प्रदर्शन के माध्यम से हिमकैट के कार्यकर्ताओं ने तिब्बत में संघर्षरत लोगों और मुक्त तिब्बत के लिए अन्यत्र लड़ रहे लोगों के समर्थन में एकजुटता व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चीन से उनकी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि चीन तिब्बत खाली कर दे।

नई दिल्ली, 4 अगस्त लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हिमालयन कमेटी फॉर एक्शन ऑन तिब्बत (हिमकैट) के लगभग 250 सदस्यों ने आज राजघाट से जंतर मंतर तक शांति मार्च में शामिल होकर तिब्बत के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन जताया। हिमालय क्षेत्र से आए बौद्ध भिक्षुओं, भिक्षुणियों और आम लोग इसमें शामिल थे। इस प्रदर्शन के माध्यम से हिमकैट के कार्यकर्ताओं ने तिब्बत में संघर्षरत लोगों और मुक्त तिब्बत के लिए अन्यत्र लड़ रहे लोगों के समर्थन में एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने तिब्बत के समर्थन में नारे लगाते हुए तथा प्रार्थनाएं गाते हुए सड़कों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चीन से उनकी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि चीन तिब्बत खाली कर दे।

एक प्रदर्शनकारी केलसांग ताशी ने कहा कि, ''हमारा चीन से कोई टकराव नहीं है। हम तिब्बत में केवल शांति और स्थिरता चाहते हैं। हम तो तिब्बत की आजादी भर चाहते हैं।'' हाल में तिब्बत में लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से निपटने के चीन सरकार के तौर तरीकों और मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन की सदस्यों ने कड़ी निंदा की।

एक अन्य प्रदर्शनकारी शांति देवी ने कहा कि ''जब तक भारत सरकार मदद नहीं करती, तिब्बत को आजादी मिलनी मुश्किल है। इसी कारण हमारा नारा है, 'तिब्बत की आजादी में भारत की सुरक्षा है'। इसीलिए भारत को हमारा समर्थन करना चाहिए।''

जैसे–जैसे ओलंपिक नजदीक आ रहा है अपनी मातृभूमि में चीन के अवैध कब्जे के खिलाफ तिब्बती अपने मुक्ति आंदोलन में जान डालने में जुट गए हैं। इस प्रकार की एकजुटता और शांति मार्चों का उद्देश्य तिब्बत मुद्दे की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकृष्ट करना है। जंतर मंतर पर तिब्बती एकता समिति ने उनका स्वागत किया।

हिमकैट के इन सदस्यों ने तिब्बती समाज द्वारा जंतर मंतर पर चलाए जा रहे अनवरत अनशन में भी सात दिन तक भाग लिया। वे 8 अगस्त को तिब्बतियों और भारतीय तिब्बत समर्थक संगठनों के सामूहिक प्रदर्शन में भी शामिल हुए। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें उनसे चीन सरकार से तिब्बत मुद्दे पर दलाई लामा के शांतिपूर्ण प्रस्ताव को अपनाने और तिब्बती जनता के मौलिक अधिकारों का हनन बंद करने की अपील करने का आग्रह किया गया। तिब्बत के हालात सुधरने तक मरते दम तक साथ देने की शपथ लेने के लिए जुटे लोगों को अरूणाचल प्रदेश की सोना रिनपोछे, माननीय लामा चोस्फेल ज़ोत्पा, भंते विश्वबंधु और डा. आनंद कुमार ने संबोधित किया।

सं. राष्ट्र कार्यालय के सामने प्रदर्शन

तिब्बती युवा कांग्रेस के महासचिव तेनजिन नॉरसांग के नेतृत्व में 11 अगस्त के दिन लगभग डेढ़ सौ कार्यकर्ताओं के एक समूह ने नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वे लोग 29 जुलाई को सौंपे अपने ज्ञापन पर की गई कार्रवाई के बारे जानकारी चाहते थे। उन्होंने तिब्बत में चीन के अनधिकृत कब्जे के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से कड़ा रुख अपनाने की मांग करते हुए नारे लगाए और चीनी व्यवस्था की निंदा की। उन्होंने मांग की कि अगर किसी प्रतिनिधि ने बाहर आकर उनके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वे वहीं भूख हड़ताल करेंगे।

तेनजिन नॉरसांग को पुलिस अधिकारी तब अंदर ले गए और संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने साथियों को बताया कि मुझे आश्वस्त किया गया है कि हमारा ज्ञापन मुख्यालय और संबद्ध मानवाधिकार समूहों को भेजा जा चुका है। संरा ने ताजा संकट के मद्देजनर आगे भी सहयोग व समर्थन का इरादा जताया है।'' उन्होंने बताया कि संरा अधिकारियों को भवन से बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से संवाद करने की अनुमति नहीं है, जिसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है। फिर भी उन लोगों ने स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की लड़ाई में तिब्बतियों का साथ देने का वादा किया है।

नेपाल में चीन विरोधी प्रदर्शनों पर पाबंदी के लिए चीन का एक और हथकंडा

मस्तांग में नेपाली जनता की भोजन सप्लाई बंद की

काठमांडू , 19 अगस्त नेपाल में लगातार चल चीन विरोधी प्रदर्शनों के लिए एक हजार से ज्यादा तिब्बती शरणार्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नेपाल पुलिस ने 19 अगस्त को 200 तिब्बती निर्वासितों को हिरासत में ले लिया जब उन्होंने चीन द्वारा अपनी मातृभूमि पर मार्च में किए गए दमन के विरूद्ध काठमांडू स्थित चीनी दूतावास की ओर मार्च करने का प्रयास किया।

प्रदर्शनकारी जिसमें भारी संख्या में भिक्षु और भिक्षुणियां भी शामिल थीं, तिब्बत की आजादी और वहां मानवाधिकारों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। यह विरोध तो मार्च से ही नियमित चल रहा था, किंतु 8 अगस्त से बीजिंग में ओलंपिक खेलों के शुरु होने के कारण इस विरोध ने नई गति पकड़ ली है। 19 अगस्त के दिन दोपहर बाद जब एक खचाखच भरी बस में बैठकर तिब्बती किंग्स पैलेस के पास पहुंचे और हतिसर रोड स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास की ओर बढ़ने लगे तब पहले से ही तैयार पुलिस भारी संख्या में वहां पहुंच गई।

तिब्बत की निर्वासित संसद ने नेपाल में रह रहे तिब्बतियों से बेहतर सलूक करने और प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार तिब्बतियों की रिहाई के लिए नेपाली प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। श्री गिरिजा प्रसाद कोईराला को 21 जून को भेजे गए पत्र में तिब्बती संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा ग्यारी ने 7वीं शताब्दी और 17वी से 20 वीं शताब्दी तक, 1959 के पूर्व के तिब्बत से नेपाल के मधुर संबंधों का उल्लेख किया।

पूर्व माओवादी विद्रोही नेता प्रचंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित होने और नई गणतांत्रिक सरकार में माओवादियों की मजबूत स्थिति के कारण ऐसा लगता है कि चीनी नीतियों के प्रभाव में नेपाल सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। तिब्बती संसद ने नेपाल के तिब्बतियों के साथ उचित व्यवहार की अपील की है।

हालांकि तिब्बतियों की आवाज हमेशा की तरह बुलंद थी, किंतु वे पिछले सप्ताह का दृश्य दोहराना नहीं चाहते थे जब पुलिस पत्रकारों पर भी टूट पड़ी थी और लगभग सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेपाली पुलिस के इस अमानवीय व्यवहार के लिए नेपाल सरकार को दुनिया भर से आलोचना झेलनी पड़ी थी। नेपाल पुलिस की इस हिंसा में 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लगता था जैसे अधिकतर पुलिस वाले मजे लेने के लिए लोगों को पीट रहे हों। एक प्रदर्शनकारी की प्रतिक्रिया थी, ''हमें समझना चाहिए कि पुलिस कितनी भी बर्बर क्यों न हो, वह नेपाल सरकार के इशारे पर काम कर रही थी। अपने ताकतवर कर्जदाता के प्रति नेपाल सरकार की चापलूसी बढ़ती जा रही है।''

इस बार प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर स्थानीय लोगों व विदेशी प्रेस तक अपना संदेश पहुंचाया कि एक ओर जहां दुनिया चीन में हो रहे ओलंपिक खेलों को देखने में व्यस्त है, वहीं तिब्बती अपनी जन्मभूमि में सताए जा रहे हैं।

भारी संख्या में नेपाल पीस ब्रिगेड व संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति के कारण नेपाल पुलिस का व्यवहार पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी अच्छा था।

तिब्बत की आजादी के समर्थन में तिब्बत में इस वर्ष मार्च में शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद से नेपाल में भी चीन–विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहने से खफा चीन ने अंततः नेपाल के सीमावर्ती जिले के निवासियों के अपनी सीमा में प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिससे कुछ सीमावर्ती इलाकों में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है।

अधिकारियों ने बताया कि नेपाल का सीमावर्ती उत्तरी जिला मस्तांग खाद्यान्न आपूर्ति के लिए पूरी तरह तिब्बत पर निर्भर है, लेकिन चीनी अधिकारियों ने छोसेर नामक सीमावर्ती चौकी से नेपाली नागरिकों का सीमा में प्रवेश रोक दिया है, जिसकी वजह से वहां भोजन का संकट पैदा हो गया है।

हिमालय की ऊंची चोटी पर स्थित मस्तांग का नेपाल की राजधानी काठमांडू से सीधा सड़क सम्पर्क नहीं है। इससे पहले नेपाली नागरिक राशन और दैनिक उपयोग की अन्य चीजों के लिए तिब्बती सीमा में प्रवेश करते रहे हैं। काठमांडू में नित्य–प्रति हो रहे चीन–विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आया है। चीन–विरोधी प्रदर्शनों ने चीनी अधिकारियों के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है।

चीन के राजदूत झेंग जियालिंग ने हाल ही में नेपाल सरकार को वहां प्रदर्शन करने वाले तिब्बतियों को सख्त सजा देने का निदेश दिया था। माओवादियों के प्रमुख श्री प्रचंड ने काठमांडू में कहा है कि माओवादियों के नेतृत्व वाली सरकार नेपाल में चीन–विरोधी आंदोलनों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।

हिमालय की ऊंची चोटी पर स्थित मस्तांग का नेपाल की राजधानी काठमांडू से सीधा सड़क सम्पर्क नहीं है। इससे पहले नेपाली नागरिक राशन और दैनिक उपयोग की अन्य चीजों के लिए तिब्बती सीमा में प्रवेश करते रहे हैं। काठमांडू में नित्य–प्रति हो रहे चीन–विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आया है। चीन–विरोधी प्रदर्शनों ने चीनी अधिकारियों के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है।

कैमरे की आं

1. नई दिल्ली में 20 अगस्त के दिन जंतर मंतर पर तिब्बती युवा कांग्रेस की साइ
2. 30 अगस्त के दिन विश्व भर में तिब्बती जनता के समर्थन में एक दिन का उप
3. तिब्बत के समर्थन में उपवास उत्सव के अवसर पर जंतर मंतर पर सर्वधर्म प्रार्थ
4. उपवास दिवस पर तिब्बती जनता के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए श्री ज
5. चीन सरकार की पाबंदियों के बावजूद ओलंपिक के दौरान तिब्बत समर्थक प्रदर्श
6. तिब्बत समर्थकों ने ओलंपिक समाप्त होने पर 25 अगस्त को पेरिस के चीनी दू
7. बीजिंग ओलंपिक के दौरान 10 अगस्त को तिब्बत के समर्थन में प्रदर्शन करते
8. ओलंपिक उद्घाटन के अवसर पर बीजिंग में तिब्बती बैनर लहराने के अपराध
9. तिब्बती जनता के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए जर्मनी के बिल्ड अखबार द्वारा
10. इस साल मार्च के तिब्बती प्रदर्शनों में चीनी पुलिस की गोली से मारे गए कुछ

♦ आंखों देखी

की आंख से

न की साइकिल रैली को झंडी दिखाती हुई सुश्री नफ़ीसा अली।

दिन का उपवास रखा गया। दिल्ली में जंतर मंतर पर उपवास स्थल का एक दृश्य।

सर्वधर्म प्रार्थना सभा में श्री बशिष्ठ नारायण सिंह और जामा मस्जिद के इमाम साहब।

लिए श्री जार्ज फर्नांडीज़ अपनी अस्वस्थता के बावजूद जंतर मंतर सभा में शामिल हुए।

मर्थक प्रदर्शन हुए। बीजिंग के एथनिक पार्क में ऐसे प्रदर्शन को रोकता पुलिस कर्मी।

के चीनी दूतावास की छत पर 'चाइना लाइज़, टिबेटंज़ डाइ' बैनर लहराया।

र्शन करते कनाडाई समर्थकों को चीनी पुलिस ने पीटा और गिरफ्तार किया।

के अपराध में निष्कासित अमेरिकी तिब्बत समर्थकों का न्यूयार्क में स्वागत समारोह।

खबार द्वारा तिब्बती चित्रों की प्रदर्शनी 'बिल्डेर आउस टिबेट' में पत्र के संपादक।

गए कुछ तिब्बतियों के फोटो लेकर 24 अगस्त को तोक्यो में प्रदर्शन।

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

ओलंपिक समारोह में राष्ट्रीयताओं की पोशाकें पहने हान चीनी बच्चे : पाखंड की हद

बीजिंग ओलंपिक के माध्यम से चीन ने औपनिवेशिक खेल खेले

ओलंपिक समारोहों में तिब्बती ऑपेरा के माध्यम से झूठा इतिहास और ओलंपिक मशाल का दुरुपयोग

बीजिंग ओलंपिक के खिलाफ दुनिया भर में चलने वाले प्रदर्शनों के बारे में चीन सरकार लगातार यह दलील देती आ रही है कि राजनीति को खेलों से अलग रखना चाहिए। लेकिन वह खुद ओलंपिक समारोहों के नाम पर लगातार अपना उपनिवेशवादी एजेंडा आगे बढ़ाने में लगी रही।

20 अगस्त, 08 बीजिंग ओलंपिक के खिलाफ दुनिया भर में चलने वाले प्रदर्शनों के बारे में चीन सरकार लगातार यह दलील देती आ रही है कि राजनीति को खेलों से अलग रखना चाहिए। लेकिन वह खुद ओलंपिक समारोहों के नाम पर लगातार अपना उपनिवेशवादी एजेंडा आगे बढ़ाने में लगी रही। इसका एक शर्मनाक उदाहरण वह तिब्बती–चीनी ऑपेरा है जो बीजिंग में खेल समारोहों के एक अंग के रूप में पेश किया गया। इस ऑपेरा का एकमात्र उद्देश्य दुनिया के सामने इस चीनी दावे को दुहराना था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है।

यह ऑपेरा चीन के तांग वंश की राजकुमारी वेन्चेंग की कहानी है जिसका विवाह सातवीं सदी के महान तिब्बती राजा स्रांगसेन गोंपो से हुआ था। सच्चाई तो यह है कि तत्कालीन चीनी राजवंश ने तिब्बत के इस विशाल साम्राज्य वाले ताकतवर राजा को खुश करने के लिए तोहफे के तौर पर उसके साथ अपनी बेटी के ब्याह का फैसला किया था। लेकिन अब चीन सरकार अपने प्रोपेगेंडा में इस रिश्ते को इस तरह से पेश करती है मानो चीनी राजकुमारी से शादी करके इस तिब्बती राजा ने चीन के सामने तिब्बत की गुलामी स्वीकार कर ली थी। बीजिंग ओलंपिक के दौरान विदेशी मेहमानों के लिए जो चुनिंदा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, यह ऑपेरा उनमें से एक था।

इस मंचन से पहले मेलानौंग ग्रैंड थिएटर के एक प्रवक्ता ने इस शो के बारे में बताया कि यह शो बीजिंग ओलंपिक का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रदर्शन होगा। यह प्रस्तुति तिब्बती व चीनी नाट्य विधा का एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण है, जिसमें ढोल और व झांझ के साथ अनूठी स्वर लहरियों का प्रयोग किया गया है।

चीन सरकार द्वारा इस ओपेरा के मंचन के फैसले का तिब्बत समर्थक पश्चिमी संगठनों ने विरोध किया और इसे 'सांस्कृतिक उपनिवेशवाद' का प्रपंच बताया। तिब्बत समर्थकों ने ओलंपिक समिति से कई बार शिकायत की है कि चीन सरकार बीजिंग ओलंपिक का दुरूपयोग तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान (सिंकियांग) और 'भीतरी' मंगोलिया पर अपने गैरकानूनी और औपनिवेशिक कब्जे को वाजिब ठहराने के लिए कर रही है।

ओलंपिक मशाल का उपनिवेशवादी हितों के लिए दुरूपयोग

चीन एक ओर तो पूरी दुनिया की इस बात के लिए निंदा कर रहा था कि बीजिंग ओलंपिक मशाल दौड़ का विरोध करके ओलंपिक खेलों का राजनीतिकीकरण किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर उसके अधिकारियों ने तिब्बत और सिंकियांग में बीजिंग मशाल दौड़ का खेलों के लिए कम और वहां अपने कब्जे को वाजिब दिखाने के लिए ज्यादा किया। तिब्बत की राजधानी ल्हासा पहुंचने पर इस मशाल जुलूस को पूरी तरह राजनीतिक अभियान में बदल दिया गया। इससे पहले सिंकियांग के मुख्य नगर काशगर और वहां की राजधानी उरुमची में भी ठीक इसी प्रकार की बपनिवेशवादी कवायद की गई।

ल्हासा में चीन ने विश्व स्तर की आलोचनाओं की परवाह किए बिना वहां ओलंपिक मशाल का प्रदर्शन किया। मार्च के अभूतपूर्व आंदोलन के बाद आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि ऐसा करना भड़काऊ होगा और सरकार द्वारा दबाई गई चीन विरोधी हिंसा फिर भड़क कर हिमालय क्षेत्र की शांति को भंग कर सकती है। लेकिन चीन सरकार ने ल्हासा को पुलिस छावनी जैसा रूप देकर समारोह करने में सफलता हासिल कर ली। कड़ी सुरक्षा में निर्वासित तिब्बती शासक और धर्मगुरु दलाई लामा के पूर्व ग्रीष्मकालीन महल नोर्बुलिंग्का से पोटला पैलेस तक पहले से चुनी हुई भीड़ की तालियों के बीच दो घंटे से अधिक की दौड़ हुई। इस दौरान बाकी ल्हासा पूर्णतया बंद रहा।

सरकारी लिस्ट से बाहर के किसी भी नागरिक को जलूस के दौरान सड़क पर नहीं आने दिया गया।

ल्हासा में मशाल दौड़ लगभग दो घंटे चली और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह एक सुनिश्चित मार्ग से बिना किसी विरोध के गुजर गई। रायटर के अनुसार तिब्बत में कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव झांग चिंग्ली ने आयोजन के बाद कहा, ''निश्चित रूप से हमने दलाई लामा की फूट डालने की योजना पर पानी फेर दिया।'' दलाई लामा के पूर्व निवास पोटला पैलेस के समक्ष बोलते हुए श्री झांग ने कहा, ''तिब्बत का आसमान कभी नहीं बदलेगा और पांच सितारों वाला लाल झंडा हमेशा उसके ऊपर लहराता रहेगा।''

बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने चिंग्ली के इस भाषण का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से शिकायत की कि ओलंपिक समारोह का राजनीजिक दुरूपयोग किया गया है।

मशाल इसके बाद चिंघाई प्रांत को बढ़ गई थी। तिब्बती निर्वासितों और मानवाधिकार समूहों ने तिब्बत में मशाल भेजने के फैसले की ओालचना करते हुए चीन सरकार पर आरोप लगाया कि मशाल दौड़ का आयोजन उसने क्षेत्र पर अपना कब्जा दर्शाने के लिए किया था।

चीन में मानवाधिकारों की स्थापना के लिए अभियान चलाने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स फार चायना के कार्यकारी निदेशक सैरॉन हॉम ने कहा, ''ओलंपकि समिति के इस तरह के उकसावे वाले फैसले से तनाव भड़क सकता है। तिब्बत समस्या के शांतिपूर्ण समाधान में बाधा पड़ सकती है। ल्हासा होकर ओलंपिक मशाल गुजारने की सरकार की जिद ने दलाई लामा के सार्थ सार्थक वार्ता के लिए जरूरी भरोसे और विश्वास को कम किया है।'' मशाल दौड़ का तिब्बती हिस्सों में आयोजन करके बीजिंग दिखाना चाहता था कि देश व खेल प्रेम में हर जाति का चीनी नागरिक एक साथ है।

न्यूयार्क स्थित स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत की कार्यकारी निदेशक ल्हाडोन टेथांग ने कहा, ''चीन सरकार ओलंपिक मशाल का इस्तेमाल दमन के एक औजार के रूप में तिब्बतियों पर कर रही है, जो अभी तक चीन की बर्बरता से कराह रहे हैं।''

निर्वासित तिब्बत सरकार के अनुसार मार्च के उपद्रव में कम से कम 209 प्रदर्शनकारी मारे गए थे। जबकि चीनी अधिकारियों ने मात्र 19 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। इन सूचनाओं की पुष्टि करना काफी कठिन है क्योंकि तिब्बत का संपर्क शेष दुनिया से अभी भी कटा हुआ है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार प्रदर्शनों के बाद से हजारों तिब्बतियों का अभी तक अता पता नहीं है और दूरस्थ तिब्बती क्षेत्रों पर आतंक का साया मंडरा रहा है।

उधर सिंकियांग में मशाल दौड़ के प्रारंभ में सैनिक शहर शिहेजी के एक कम्युनिस्ट उच्चाधिकारी सांग झिंगुओ ने मशाल का स्वागत किया। यह शहर चीनी सेना द्वारा बसाया और बनाया गया नया शहर है। यहां स्थानीय उईगुर लोगों का अनुपात केवल 6 प्रतिशत है। बाकी लोग चीन से लाए गए सैनिक हैं। यहां ओलंपिक मशाल दौड़ का झिंजियांग में तीसरा और अंतिम दिन था। इस शहर में चीनी नागरिकों ने उत्साह से मशाल का स्वागत किया। लेकिन काशगर और राजधानी उरुमची में मशाल दौड़ के दौरान शहर के लगभग सभी नागरिकों को अपने घरों में बंद रहने के आदेश दिए गए थे ताकि वे मशाल का विरोध न कर सकें। इस यात्रा के दौरान चीन सरकार ने बीजिंग से कुछ विदेशी पत्रकारों को भी इन समारोहों की रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि ये पत्रकार स्थानीय लोगों से न मिल पाएं। काशगर और उरुमची में सरकारी एजेंटों ने पत्रकारों को पूरी तरह घेरे रखा। बाद में उरुमची के ठीक उत्तर पश्चिम स्थित माउंटेन रिसॉर्ट टाऊन चांग्जी में मशाल ने अपना अंतिम पड़ाव किया। यहां से मशाल तिब्बती क्षेत्र की राजधानी ल्हासा के लिए रवाना हुई।

सिंकियांग में आजाद पूर्वी तुर्कीस्तान की स्थापना के पक्षधर जर्मनी स्थित निवार्सित संगठन उईगुर कांग्रेस के अनुसार चीन ने वहां 25 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं जो पूर्णतया एक उपनिवेशी बल जैसा व्यवहार करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एफपी से कहा, ''सिंकियांग प्रोडक्शन कॉर्प्स का काम उईगुर राष्ट्रीयता वाले जातीय समूहें का दमन और पूर्वी तुर्कीस्तान के दीर्घकालीन उपनिवेशीकरण की पुख्ता व्यवस्था करना है।

सिंकियांग हिस्से की संवेदनशीलता इस वर्ष के प्रारंभ में ही बढ़ गई थी जब बीजिंग ने दावा किया था कि उसने खेलों को निशाना बनाने वाले 'आतंकवादियों के सिंकियांग स्थित ठिकानों को नष्ट कर दिया है।'' उइगुर कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार ''उईघर भय के माहौल में रह रहे हैं। उनका उत्पीड़न करने के अलावा उन्हें अपने ही देश में अर्थहीन बना देने और उनकी सांस्कृतिक पहचान मिटाने का काम किया जा रहा है जिससे धीरे–धीरे उइगुर संस्कृति, उनकी पहचान, धार्मिक मान्यताओं व आर्थिक अधिकारों के मूल तत्व ही नष्ट हो जाएंगे।

काशगर और राजधानी उरुमची में मशाल दौड़ के दौरान शहर के लगभग सभी नागरिकों को अपने घरों में बंद रहने के आदेश दिए गए थे ताकि वे मशाल का विरोध न कर सकें। इस यात्रा के दौरान चीन सरकार ने बीजिंग से कुछ विदेशी पत्रकारों को भी इन समारोहों की रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि ये पत्रकार स्थानीय लोगों से न मिल पाएं।

बीजिंग की तिब्बत में 10 लाख हान चीनियों को बसाने की योजना

ओलंपिक के बाद अब चीन की प्राथमिकता तिब्बत जैसे 'समस्याग्रस्त' क्षेत्र का 'इलाज' करना होगी

तिब्बत के निर्वासित शासक दलाई लामा ने कहा है कि चीन ओलंपिक खेलों के बाद तिब्बत में 10 लाख हान चीनियों को बसाने की योजना बना रहा है। वहां चीनियों को बसाने का उद्देश्य तिब्बती संस्कृति और पहचान को नष्ट करना है। चीन की हान वर्चस्व वाली व्यवस्था में अन्य 55 राष्ट्रीयताओं के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए हान जनसंख्या को हथियार की तरह पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है।

ओलंपिक खेलों के बाद चीन सरकार का अगला निशाना तिब्बत है। तिब्बत में चीन विरोधी वातावरण को चीन सरकार के समर्थन में बदलने के लिए चीन सरकार वहां चीनियों को बसाने के उस अभियान को नई गति देने जा रही है जो ओलंपिक में व्यस्तता और इस कारण दुनिया भर की चीन पर निगाहों की वजह से धीमा पड़ा हुआ था। तिब्बत के निर्वासित शासक दलाई लामा ने कहा है कि चीन ओलंपिक खेलों के बाद तिब्बत में 10 लाख हान चीनियों को बसाने की योजना बना रहा है। वहां चीनियों को बसाने का उद्देश्य तिब्बती संस्कृति और पहचान को नष्ट करना है। चीन की हान वर्चस्व वाली व्यवस्था में अन्य 55 राष्ट्रीयताओं के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए हान जनसंख्या को हथियार की तरह पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है।

दलाई लामा ने गार्डियन अखबार में प्रकाशित इंटरव्यू में कहा, ''हमें जानकारी मिली है कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में ओलंपिक खेलों के बाद 10 लाख चीनी बसाए जाएंगे। इस तरह के कदमों से तिब्बत में हान चीनी बहसंख्यक हो जाएंगे जबकि तिब्बती अपने ही देश में महत्वहीन अल्पसंख्यक बन जाएंगे। इससे वहां स्वायत्ता के विचार का आधार ही अर्थहीन हो जाएगा।'' उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में तिब्बत में किए जा रहे विकास से तिब्बत में बसने वाले चीनियों की बाढ़ आ गई है। लेकिन इनके सही आंकड़ों पर चीन और विरोधियों के बीच भारी विवाद है। सन् 2000 की जनगणना के मुताबिक, उस क्षेत्र में 24 लाख तिब्बती और 159,000 हन चीनी थे। ल्हासा में अब हन चीनियों की आबादी तिब्बतियों से अधिक हो गई है। लेकिन इसके बावजूद चीन इस बात से इनकार करता है कि तिब्बती संस्कृति और पहचान को नष्ट करने के लिए वहां तिब्बत में चीनियों को बसाने की नीति चलाई जा रही है। उसका कहना है कि इसके विपरीत वहां आर्थिक विकास और निवेश किया जा रहा है जिससे उस क्षेत्र को फायदा हो रहा है।

दलाई लामा ने कहा कि भारी संख्या में जनसंख्या के हेर फेर से तिब्बत के पर्यावरण पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तिब्बती प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से तिब्बती पहाड़ी क्षेत्रों से बहने वाली यांगत्सी, पीली नदी, सिंधु नदी, मेकोंग और गंगा के पानी की गुणवत्ता तथा बहाव के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा, ''तिब्बती क्षेत्र में अंधाधुंध खनन, जंगलों की कटाई और समुचित योजना के बिना सिंचाई की जा रही है।'' दलाई लामा ने आशंका जताई है कि यदि उनके प्रतिनिधियों और बीजिंग के बीच बातचीत टूट गई तो फिर से हिंसा भड़क सकती है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि जल्दी ही चीनी अधिकारियों के साथ बीजिंग में लंबी वार्ता का नया दौर शुरू हो सकता है।

पूर्व तिब्बती शासक और आध्यात्मिक नेता ने कहा कि वार्ता टूटने पर प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ''मैं अतीत के अनुभव से कह सकता हूं कि वार्ता टूटने पर न केवल जबर्दस्त प्रदर्शन होगा, बल्कि हिंसा शुरू होने का भी भय है। इस साल मार्च में फैली अशांति सहित पिछले प्रदर्शन इसके उदाहरण हैं जिन्होंने गंभीर हिंसा का रूप ले लिया था। यह बहुत दुखद है कि उनमें कई तिब्बतियों की जानें चली गईं। चीन की तरफ से भी कई लोग हताहत हुए।''

तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्राउन के साथ उनकी पहली मुलाकात बहुत उपयोगी रही। ब्राउन ने तिब्बत की स्थिति पर 'वाजिब चिंता' व्यक्त की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि ब्राउन के साथ उनकी पहली मुलाकात 'बहुत अच्छी' रही। ब्राउन ने तिब्बत की स्थिति पर 'वाजिब चिंता' व्यक्त की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि ब्राउन ने लामबेथ पैलेस में तिब्बती नेता के साथ 30 मिनट तक बातचीत की जिसमें रचनात्मक चर्चा हुई। लामबेथ पैलेस लंदन में कैंटरबरी के आच बिशप का आधिकारिक निवास है।

चीन का विरोध : फ्रांस में पुजारी ने खुद को चर्च में बंद किया

नई दिल्ली, 12 अगस्त फ्रांस के एक पुजारी ने पश्चिमी पोलैंड के एक चर्च में खुद को बंद कर लिया और घोषणा कर दी कि चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ वह बीजिंग में ओलंपिक खेल जारी रहने तक भूख हड़ताल पर रहेगा। फादर एड नाम से चर्चित इस पुजारी ने चर्च के पास स्थित एक खंभे पर तिब्बती झंडा फहरा दिया था। वह चीनी उत्पादों के विरूद्ध लंबे समय से अभियान चला रहा है। यहां तक कि वह चीन से सस्ती छपवाई के नाम

पर बाइबिल और दूसरी उपासना पुस्तकें मंगवाने का भी यह कहकर विरोध करता है कि भगवान के संदेश में अमानवीय मजदूरी का इस्तेमाल पाप है। अपने इस नए विरोध के बारे में पुजारी ने कहा कि उसे आशा है कि उसके रूख और प्रार्थना से 'दमन के शिकार' तिब्बत के प्रति समर्थन का भाव लोगों में पैदा होगा।

कनाडा तिब्बत कमेटी और एसएफटी की वैंकूवर स्थित शाखाओं के कार्यकर्ता कल चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर इस संदेश के साथ जमा हुए ''हमें खेद है कि पीआरसी तुम अस्वस्थ हो।'' दूतावास को चीन सरकार के स्वस्थ होने के कार्ड दिए गए, जिसमें पीआरसी को उत्पीड़न, धार्मिक दमन, इलेक्ट्रानिक जासूसी, मीडिया पर पाबंदी और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी बीमारियों से जल्द उबरने की कामना की गई थी। उन्होंने वाणिज्य दूतावास पर अनिश्चित काल का धरना देने का फैसला किया।

स्थानीय तिब्बत समूहों के समर्थन से आस्ट्रियन तिब्बती समुदाय ने भी वियना में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। इसमें तिब्बती व गैर तिब्बती कुल तीन से पांच सदस्य शामिल रहेंगे। ये लोग आस्ट्रिया सरकार से आग्रह करेंगे कि वह हाल ही में गिरफ्तार व निष्कासित तिब्बतियों, विशेषकर जिन्हें जोखांग और लाब्रांग ताशीखेल में पत्रकारों से बात करते टीवी पर देखा गया था उनकी खोज खबर के लिए चीन सरकार से सार्थक वार्ता करें। 21 अगस्त को सुबह पत्रकार वार्ता के बाद विएना के केंद्रीय इलाके में अनशन की शुरुआत की गई।

टू टू, हैवेल ने खेलों के दौरान आवाज उठाने की अपील की

प्राग पूर्व चेक राष्ट्रपति वैक्लाव हैवेल और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टू टू ने बीजिंग ओलंपिक के दौरान चीन में मानवाधिकारों को लेकर ओलंपिक खिलाड़ियों से चर्चा की। मानवाधिकारों के पैरोकार श्री हैवेल जिन्हें उनकी सरकार के पतन के बाद कम्युनिस्ट सरकार ने 1889 में जेल में डाल दिया था और दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप टू टू ने एक खुले पत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को चीन में आजादी का गला घोटने की जानकारी खिलाड़ियों को देनी चाहिए।

पत्र में कहा गया है, ''यह आवश्यक है कि सभी ओलंपिक खिलाड़ी चीन के असल हालात को जानें और अपनी आत्मा की आवाज पर जब भी, जहां भी अवसर मिले मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाएं।'' उन्होंने आगे कहा कि, ''हमारी मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसे संभव बनाए।''

8 से 24 अगस्त तक आयोजित खेलों के पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने एक प्रमुख विरोधी नेता की गिरफ्तारी और कई वेबसाइटों पर प्रतिबंध तथा चीन की विदेश नीति व मानवाधिकार का समर्थन करने के सवाल पर बीजिंग की आलोचना की है। हालांकि आईओसी ने खेलों और उससे संबद्ध समारोहों को राजनीति से मुक्त रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। पत्र में कहा गया है कि खिलाड़ियों को आवाज उठानी होगी और आईओसी को इसके लिए उन्हें अनुमति देनी चाहिए। पत्र पर चीनी विरोधी नेता वेई जिंगसेंग तथा यूरोपियन संसद के वाइस प्रेसीडेंट एडवर्ड मेकमिलन स्कॉट के भी हस्ताक्षर हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में बोलने को ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

मानवाधिकारों की बात करना कोई राजनीति नहीं है। केवल तानाशाह के राज में ही ऐसा माना जाना संभव है। मानवाधिकारों की आवाज उठाना तो हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रपति के रूप में 1989–2003 के बीच श्री हैवेल निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामा से अपने निजी संबंधों के कारण चीन सरकार को अनेक बार नाराज़ कर चुके हैं।

40 से अधिक ओलंपिक खिलाड़ियों ने तिब्बती गीत डाउनलोड किए

वाशिंग्टन डीसी, 18 अगस्त अमेरिका, कनाडा, और कई यूरोपियन देशों तथा जापान में खूब बिक रहा रॉक डाउनलोड 'सांग्स फॉर टिबेट –– द आर्ट ऑफ पीस' को बीजिंग ओलंपिक में भाग ले रहे 40 से अधिक खिलाड़ियों ने डाउनलोड किया है। यह एलबम पहले हफ्ते की बिक्री में ही बिलबोर्ड अल्बम डाउनलोड चार्ट्स के चौथे पायदान पर पहुंच गया। इस तथ्य से तिलमिलाए चीन के सरकारी मीडिया ने एक भड़काऊ ऑनलाइन लेख प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया था कि बहुत से चीनी नागरिकों ने इस प्रोजेक्ट की निंदा की है ।

दुनियाभर में सौ से अधिक डाउनलोड साइट्स व ऑन लाइन विक्रेता इस अल्बम को बेच रहे हैं। बीस संगीतकारों ने इसमें भागीदारी की है जिसमें स्टिंग, डेव मैथ्यूज, एलानिस मॉरिस्सेट, जॉन मायर और मॉबी शामिल हैं। प्रोजेक्ट के जनक आर्ट ऑफ पीस फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक माइकेल वोह्म ने आज कहा, ''हम इस बात से बहुत खुश हैं कि

दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेसमंड टू टू ने एक खुले पत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को चीन में आजादी का गला घोटने की जानकारी खिलाड़ियों को देनी चाहिए। पत्र में कहा गया है, ''यह आवश्यक है कि सभी ओलंपिक खिलाड़ी चीन के असल हालात को जानें और अपनी आत्मा की आवाज पर जब भी, जहां भी अवसर मिले मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाएं।''

खेलों से प्यार की आड़ में मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती। बीजिंग ओलंपिक मानवाधिकार के मुद्दों संबंधी विवाद पर शुरू से ही घिरा हुआ है। ''मैं पुरुषों और महिलाओं खिलाड़ियों को सलाह दूंगा कि वे वस्तुस्थिति पर गौर करें, न कि उससे मुंह मोड़ लें।'' अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हर खिलाड़ी को अपने ढंग से एक संकेत जरूर देना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम तिब्बत के लोगों को न भूलें जो अपने सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।''

ओलंपिक खिलाड़ियों ने इस विशिष्ट अल्बम को डाउनलोड करने के अवसर का लाभ उठाया। इससे इस बात का संदेश भी गया कि तिब्बतियों के प्रति एकजुटता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन नहीं किया जा सकता। ''

इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने वाले ''इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत'' की केट सैंडर्स ने कहा, ''इस वक्त चीनी इंटरनेट यूजर्स और सरकारी वेबसाइट की इस अल्बम के प्रति दुश्मनी स्वभाविक है। इससे तिब्बत को समर्थन देने के किसी प्रयास को दबाने और बीजिंग सरकार द्वारा चीनी जनता को बहकाने की मंशा भी साफ होती है।'' डेव मैथ्यूज, जॉन मायर और मॉबी ने गीतों के रिलीज में भी भूमिका निभाई।

तेनजिन त्सुंदू को मंडी जेल से कांगड़ा पुलिस को सौंपने की तैयारी

धर्मशाला, 11 अगस्त तिब्बती मुक्ति आंदोलन के एक लोकप्रिय तिब्बती कार्यकर्ता, कवि और लेखक तेनजिन त्सुंदू को नौ दिन पुलिस हिरासत में रहने के बाद सोमवार को मंडी जेल से रिहा कर दिया गया। उनके ऊपर भारतीय सीमा पार कर तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ प्रदर्शन करने का प्रयास करने का आरोप था।

श्री त्सुंदू ने फोन पर फायूल को बताया, ''अभी तक तो मेरे विरूद्ध कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है किंतु देखिए कांगड़ा पुलिस की गिरफ्त में पहुंचने के बाद क्या होता है।'' फोन पर बात करते समय वह चार सिपाहियों के साथ एक पुलिस वैन में धर्मशाला के रास्ते में थे। पुलिस ने पहले श्री त्सुंदू को तिब्बत में घुसने के प्रयास के कथित आरोप में तीन अगस्त को हिमाचल के भुंतर एअरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। उन्हें कुल्लू थाने ले जाया गया, लेकिन अगले दिन रिहा कर दिया गया। चार अगस्त को उन्हें दोबारा मंडी से फिर पकड़ लिया गया और जब उन्होंने न्यायिक हिरासत में अन्न–जल लेने से इनकार कर दिया तो मंडी जेल में बंद कर दिया। उनके अनुसार चौथे दिन उन्हें मंडी जोनल अस्पताल पहुंचाया गया और जबर्दस्ती खिलाने की भी सलाह दी गई। इसके बाद उन्हें फिर जेल भेज दिया गया।

श्री त्सुंदू ने कहा कि वह मंडी, पंडोह और रिवाल्सर के स्थानीय तिब्बतियों के आभारी हैं जिन्होंने उनकी सुरक्षित रिहाई में मदद की और जेल में उनसे मिलने भी आए। ऐसा पहली बार नहीं था कि श्री त्सुंदू अपनी मातृभूमि में घुसने के प्रयास में गिरफ्तार हुए हों। वह इस वर्ष मार्च में धर्मशाला से 'मार्च टू तिब्बत'' आंदोलन के अंतर्गत गठित कई दलों से एक मुख्य जत्थे के नेता भी थे। उन्हें और उनके साथियों को 110 दिन तक मार्च करने के बाद धारचूला पहुंचने पर भारतीय पुलिस ने वहां रोक दिया था जो सीमा से पहले अंतिम भारतीय बस्ती है।

श्री त्सुंदू जो फ्रेंड्स आफ तिब्बत इंडिया के महासचिव हैं, ने फायूल से कहा, ''मुझे जबर्दस्ती खाना खिलाने और मनमाने ढंग से हिरासत में रखने की घटना से मुझे अहसास हुआ कि हमारे (तिब्बतियों) पास न तो अपना देश है न ही स्वतंत्रता। लेकिन तिब्बत में तो हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हैं।''

उन्होंने आशंका जताई कि बीजिंग ओलंपिक समाप्त होने के बाद तिब्बत में तिब्बतियों की दशा और बिगड़ेगी। उन्होंने कहा, ''यही बात मुझे कुछ और करने के लिए प्रेरित करती है और मेरा इरादा अटल है।'' श्री त्सुंदू अपने खतरनाक इरादों के लिए उस समय से जाने जाते हैं, जब जनवरी 2002 में उन्होंने मुंबई में ओबरॉय टावर्स होटल की 14वीं मंजिल पर ''फ्री तिब्बत'' लिखा झंडा और बैनर टांग दिया था। उस समय चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री झू रांगजी भारत में मुंबई में थे और होटल के भीतर एक बिजनेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

तेनजिन ने 1999 में अपना पहला कविता संग्रह ''क्रासिंग द बॉर्डर'' प्रकाशित किया था। उनके निबंध ''माई काइंड ऑफ एक्जाइल'' को सर्वश्रेष्ठ गैरकथा आउटलुक/पिकार्डार अवार्ड मिला था।

यूरोपीय संसद अध्यक्ष ने ओलंपिक विरोध की आवाज बुलंद की

यूरोपियन संसद के अध्यक्ष गर्ट पोएटरिंग ने बीजिंग ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने का आह्वान किया है।

जर्मन समाचार पत्र बिल्ड अम ज़ोन्टाग के 3 अगस्त के अंक में छपे अपने लेख में इस मध्य दक्षिण मार्गी राजनेता ने कहा कि खेलों से प्यार की आड़ में मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती। बीजिंग ओलंपिक मानवाधिकार के मुद्दों संबंधी विवाद पर शुरू से ही घिरा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि, ''मैं पुरुषों और महिलाओं खिलाड़ियों को सलाह दूंगा कि वे वस्तुस्थिति पर गौर करें, न कि उससे मुंह मोड़ लें।''

उन्होंने सलाह दी है कि चीन की राजधानी में शुरु हो रही अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हर खिलाड़ी को अपने ढंग से एक संकेत जरूर देना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम तिब्बत के लोगों को न भूलें जो अपने सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।''

श्री पाएटरिंग की टिप्पणी उस समय आई जब चीनी अधिकारियों द्वारा खेलों की कवरेज में इंटरनेट के गैर प्रतिबंधित इस्तेमाल से मुकर जाने के बाद जर्मनी में इस इंटरनेट सेंसरशिप को लेकर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। जर्मन विदेशमंत्री फ्रैंक वाल्टर ने डेर पोगल समाचार पत्रिका में प्रतिक्रिया व्यकत की, ''मेरी समझ से बाहर है कि चीन सरकार ने एक बार फिर इंटरनेट के प्रयोग पर क्यों अंकुश लगा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय बहस को हवा दे दी।'' अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी इस विवाद में फंस गई है। उस पर आरोप है कि इंटरनेट प्रयोग के बारे में उसने चीन सरकार से समझौता कर लिया है।

जर्मन रेडियो डायट्शे वैले की रिपोर्ट के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल के जर्मन प्रभाग की प्रमुख बारबरा ने जर्मन समाचार पत्र नॉय ओस्नाब्रूएकर साईटुंग अखबार में कहा, ''आईओसी ने न तो कभी कोई स्पष्ट कदम उठाया और न ही चीनियों पर मानवाधिकारों व प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी वायदों पर कायम रहने के लिए दबाव ही डाला।'' आईओसी के मुखिया जैक्स रॉग जिन्होंने खेलों के दौरान चीन में मुक्त इंटरनेट सुविधा का वायदा पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने किया था, अपनी फजीहत के बाद सफाई दी कि इंटरनेट प्रयोग के बारे में चीन से कोई गुपचुप समझौता नहीं हुआ है।

श्री रॉग ने कहा ''मैं ऐसी कोई सफाई नहीं देने जा रहा, जिसके लिए आइओसी जिम्मेदार नहीं है। हम चीन में इंटरनेट नहीं चला रहे हैं।'' चीन में मानवाधिकारों की स्थिति और इस साल की शुरुआत में तिब्बती प्रदर्शनकारियों के दमन से उपजे विवाद के कारण टिप्पणीकार इस बात को लेकर बंटे हुए हैं कि क्या चीन को ओलंपिक के आयोजन की अनुमति मिलनी चाहिए।

अप्रैल में यूरोपियन संसद ने एक संकल्प पारित किया था कि यदि चीन तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से वार्ता नहीं शुरु करता है तो यूरोपीय नेताओं द्वारा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन ईयू ट्रेड कमिश्नर पीटर मैंडेल्सन की दलील थी कि, ''हमें अपने मूल्यों और मान्यताओं के साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें चीन के साथ काम करने, साथ–साथ खड़ा होकर उसे कामयाब भी बनाना है।

तिब्बत के छात्रों ने अनूठी कला प्रतियोगिता के माध्यम से चिंता प्रकट की

कला के माध्यम से बच्चों ने गुलाम तिब्बत की भीतरी हालत और तिब्बत के दर्द को व्यक्त किया

काठमांडू, काठमांडू स्थित विभिन्न तिब्बती स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों ने सामतेनलिंग मठ में आयोजित एक अनूठी कला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 'द वॉयस ऑफ तिबेतन चिल्ड्रेन फॉर तिब्बत' शीर्षक की इस प्रतियोगिता में 50 से अधिक तिब्बती छात्रों ने हिस्सा लेकर चित्रों, कार्टूनों और पेंटिंग के जरिये तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की।

इस प्रतियोगिता में 10 स्कूलों के दस–दस छात्र शामिल हुए। इन स्कूलों में स्रोंगत्सेन स्कूल, मंजुगोक्षा स्कूल, नामग्याल मिडल स्कूल, नामग्याल हाईस्कूल एवं अतिषा प्राइमरी स्कूल भी थे।

बच्चों ने जो पेंटिंग बनाईं उनमें मठों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों, पोताला पैलेस, तिब्बती ध्वज, पहाड़ियों, चीनी सैनिकों के तिब्बतियों पर हमला करते चित्रों के अलावा 'फ्री तिब्बत' और 'तिब्बत में हत्या बंद करो' जैसे संदेश भी शामिल थे। एक छात्र ने पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते युवा भिक्षु की तस्वीर बनाई जो ध्यान में लीन है और तिब्बत की आजादी के लिए प्रार्थना कर रहा है। तस्वीर में एक कपोत को चीनी ध्वज को तिब्बत से दूर ले जाते और कहीं दूर से से तिब्बती ध्वज को तिब्बत में लाते दिखाया गया है।

एक अन्य छात्रा ने अपनी पेंटिंग में चीनी सैनिकों को तिब्बतियों पर गोलियां चलाते दिखाया है। उसका कहना है कि उसके पिता ने उसे तिब्बत में हो रहे वर्तमान चीनी दमन के बारे में सब कुछ बताया हुआ है और वह तिब्बत के भीतर की स्थिति के बारे में अच्छी तरह जानती है।

हाल ही में तिब्बत में उत्पन्न अशांति एवं दुनिया भर में तिब्बत की आजादी से संबंधित आंदोलन के पुनर्जीवित होने से तिब्बती बच्चों में अपनी जड़ों और संस्कृति के बारे में पहले से अधिक उत्सुकता पैदा हुई है। एक ऐसा ही उदाहरण है श्रीमती ग्याल्त्सेन त्सुंदु का जो पूर्व राजनीतिक बंदी हैं और अब अपने पति एवं चार बच्चों के साथ बौद्धा में रहती हैं। उन्होंने तिब्बती वेब पत्रिका फायुल को बताया, ''सभी तिब्बती अभिभावकों को अपने बच्चों को तिब्बत को लेकर जारी संघर्ष के बारे में जानकारी अवश्य देनी चाहिए, ताकि हम अपनी पहचान न खोएं।''

बच्चों ने जो पेंटिंग बनाईं उनमें मठों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों, पोताला पैलेस, तिब्बती ध्वज, पहाड़ियों, चीनी सैनिकों के तिब्बतियों पर हमला करते दिखाया है। एक छात्र ने पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते युवा भिक्षु की तस्वीर बनाई जो ध्यान में लीन है और तिब्बत की आजादी के लिए प्रार्थना कर रहा है। तस्वीर में एक कपोत को चीनी ध्वज को तिब्बत से दूर ले जाते और कहीं दूर से से तिब्बती ध्वज को तिब्बत में लाते दिखाया गया है।

मानवाधिकार और तिब्बत पर ओलंपिक खिलाड़ियों की राष्ट्रपति हू से अपील

तिब्बत की जनता के मानवाधिकारों के सम्मान और शांतिपूर्ण समाधान निकालने की सलाह

बर्लिन, 6 अगस्त बीजिंग खेलों में भाग लेने वाले 40 खिलाड़ियों सहित 127 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर करके चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ से तिब्बत समस्या के शांतिपूर्ण समाधान और चीन में मानवाधिकारों के सम्मान की मांग की है। हस्ताक्षर करने वालों में विशव चैंपियन क्रोएशिया के हाई जंपर ब्लांका व्लासिक, 110 मीटर हर्डल्स के विश्व रिकार्डधारी क्यूबा के डेरॉन रॉबल्स, अमेरिकी 400 मीटर धावक डीडी ट्रॉटर, और पनामा के लांग जंपर ईरविंग सालाडिनो शामिल हैं।

जर्मनी में 'शांति के लिए खेल' द्वारा तैयार अपने पत्र में खिलाड़ियों ने कहा है कि उनके द्वारा इंगित मुद्दों पर उठाए गए कदमों का ''ओलंपिक खेलों के नतीजों तथा भविष्य में विश्व में चीन की छवि पर गहरा असर पड़ेगा।''

अपील में कहा गया है कि, तिब्बत मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और तिब्बत समेत आपके देश चीन में जिन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है उनमें मानवाधिकारों के मौलिक सिद्धांतों को मुहैया कराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और वैचारिक स्वतंत्रता की रक्षा, मानवाधिकार समर्थकों का प्रताड़न रोकना और उन्हें जेल नहीं भेजना तथा मृत्यु दंड समाप्त करना जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।

अपील में कहा गया है कि, तिब्बत मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और तिब्बत समेत आपके देश चीन में जिन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है उनमें मानवाधिकारों के मौलिक सिद्धांतों को मुहैया कराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और वैचारिक स्वतंत्रता की रक्षा, मानवाधिकार समर्थकों का प्रताड़न रोकना और उन्हें जेल नहीं भेजना तथा मृत्यु दंड समाप्त करना जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।

दलाई लामा ने बर्मा के चक्रवात पीड़ितों के लिए राशि प्रदान की

तिब्बत के निर्वासित शासक और सर्वोच्च धार्मिक गुरू परमपावन दलाई लामा ने बर्मा में आए चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए लोगों को राहत पहुंचाने एवं पुनर्निर्माण के कार्य के लिए पांच लाख रुपये का सहयोग प्रदान किया है।

बर्मा की निर्वासित सरकार द नेशनल कॉलिशन गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ बर्मा (एनसीजीयूबी) के एक मंत्री डॉ. टींट स्वे ने बताया कि नोबल पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने बर्मा के लोगों के लिए यह सहयोग राशि प्रदान की है। डॉ. स्वे ने ही यह सहयोग राशि हासिल की है। उन्होंने कहा, ''यह बर्मा की जनता के लिए प्रोत्साहन है। यह राशि ऑल बर्मा मौंक एलायंस को भेज दी जाएगी।

बर्मा के तटीय इलाके इरावाडी और रंगून मंडल में चक्रवाती तूफान आने के बाद से दलाई लामा की ओर से दूसरी बार सहयोग राशि प्रदान की गयी है। तूफान के तुरंत बाद दलाई लामा ने तूफान पीड़ितों के लिए 50 हजार रुपये का सहयोग किया था।

तिब्बत में दमन रोकने के लिए चीन से मानवाधिकार समूहों का अनुरोध

धर्मशाला, 2 अगस्त तिब्बती सॉलिडारिटी कमेटी ने दुनिया के देशों, विशेषकर मानवाधिकार संगठनों से अनुरोध किया है कि तिब्बती लोगों के दमन की सभी कार्रवाइयां तत्काल रोकने और मौलिक मानवाधिकारों व धार्मिक स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए चीन पर दबाव डालें।

कमेटी द्वारा 2 अगस्त को जारी एक प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि महान बौद्ध भिक्षु दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने चीन की प्राचीन सभ्यता को उचित मान सम्मान व चीनी लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बीजिंग ओलंपिक खेलों को शुरू से ही समर्थन दिया है। लेकिन ओलंपिक सुरक्षा के नाम पर चीन सरकारने ऐसा बंदोबस्त कर दिया है जिससे तिब्बती लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार प्रभावित हुए हैं।

तिब्बती भिक्षुओं को देशभक्ति परीक्षण से गुजरना पड़ेगा

(गन्नान, गांसू से रायटर संवाददाता लूसी हार्नबी की रिपोर्ट पर आधारित)

इस साल मार्च में तिब्बत में हुए व्यापक प्रदर्शनों के कई महीने बाद अब भिक्षुओं का कहना है कि उन्हें भिक्षु बने रहने के लिए संभवतः सितम्बर में एक 'देशभक्ति परीक्षा' से गुजरना पड़ेगा। इस इलाकें में इस बात से तनाव है कि बौद्धभिक्षुओं पर प्रदर्शनों के लिए अब जुर्माना लगाया जा रहा है और उनकी देशभक्ति की जांच की तैयारी चल रही है।

एक युवा भिक्षु ने कहा ''हम जानते हैं कि हमारे इलाके में क्या–क्या हुआ और तिब्बत किस तरह चीन का हिस्सा बना। अब वे हमें समझाना चाहते हैं कि हमलोग आतंकवादी या पृथकतावादी हैं।''

एक युवा भिक्षु ने सवाल पूछने पर अपना मुंह हाथों से ढककर चेहरा झुका लिया और कहा, ''जांच में शामिल होने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए तो तिब्बती कहते हैं कि हम आजाद नहीं है। हम तिब्बतियों को अपने ही देशा में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है।''